



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 673]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2015/कार्तिक 8, 1937

No. 673]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2015/KARTIKA 8, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2015

सं. 53/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 825(अ).— नामित प्राधिकारी ने पाकिस्तान, साउदी अरब, और संयुक्त अरब अमीरात (जिसे इसके बाद विषयगत देशों कहा गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “क्लियर फ्लोट ग्लास की मामूली मोटाई, 4 मिमी. से 12 मिमी. (दोनों को शामिल करते हुए) जिसे बीआईएस 14900:2000 के अनुसार मामूली मोटाई माना जाता है” (जिसे इसके बाद संबद्ध माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतदपश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 के अंतर्गत आती हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना फा. सं. 14/19/2013-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विषयगत माल का विषयगत देश से उसकी सामान्य से कम कीमत पर भारत को नियात किया गया है जिससे यह विषयगत माल की भरमार हो रही है;
- (ii) घरेलू उद्योग को विषयगत माल के मामले में सारवान क्षति हुई है; और
- (iii) विषयगत देशों से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तु के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

और जहां कि अभिहीत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने विषयगत माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 48/2014-सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 11 दिसम्बर, 2014, जिसे सा०का०नि० 885(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 11 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है।

और जहां कि मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान (निर्यातक) ने अपने द्वारा किये गये विषयगत माल के आयात की सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित वस्तुओं के अभिज्ञान, आकलन और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 22 की दृष्टि से समीक्षा करने का अनुरोध किया था और नामित प्राधिकारी ने अपने नये शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 15/16/2015- डीजीएडी, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खण्ड I में दिनांक 24 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित किया गया था में उपर्युक्त पार्टी द्वारा किये गये विषयगत माल के सभी निर्यातों का तब तक के लिए अनंतिम आकलन किये जाने की सिफारिश की थी जब तक कि इसके द्वारा समीक्षा का काम पूरा नहीं हो जाता है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप-नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने नामित प्राधिकारी की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, आदेश देती है कि नामित प्राधिकारी के द्वारा दी गई उपर्युक्त समीक्षा के परिणामों के विचाराधीन रहने के कारण, विषयगत माल पर, जब यह विषयगत देश में मूलतः उत्पादित हो या वहां से निर्यातित हो और उक्त निर्यातक अर्थात् मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान के माध्यम से निर्यात किया गया हो और भारत में उसका आयात हुआ हो तब तक अनंतिम आकलन लागू रहेगा जब तक कि यह समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यदि नामित प्राधिकारी के जांच कार्य के पूरा हो जाने पर निश्चयात्मक प्रतिपाटनशुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो यह अनंतिम आकलन उस प्रतिभूति और गारंटी के अधीन रहेगा जिसे यथेष्ट सीमा शुल्क प्राधिकारी किसी अक्षमता, यदि हो हो, की स्थिति में भुगतान किये जाने के लिए उचित समझता है।

3. सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा समीक्षा कार्य को पूरा किये जाने के बाद दी गई सिफारिशों के मामले में, आयातकर्ता उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से, प्रति पाटन शुल्क के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करेगा जिसकी समीक्षा में सिफारिश की गई हो और जिसे विषयगत माल के सभी आयात पर, जब उनका मूलतः उत्पादन विषयगत देश में हुआ हो अथवा वहां से उसका निर्यात हुआ हो और उसका निर्यात उक्त निर्यातकर्ता अर्थात् मैसर्स तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पाकिस्तान द्वारा किया गया हो और भारत में आयात हुआ हो, लगाया गया हो।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2015

No. 53/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 825(E).— Whereas, in the matter of import of Clear Float Glass of nominal thickness ranging from 4 mm to 12 mm (both inclusive), the nominal thickness being as per BIS 14900:2000 (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the headings 7003, 7004, 7005, 7009, 7013, 7015, 7016, 7018, 7019, 7020 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Pakistan, Saudi Arabia and UAE (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, *vide* its final findings, *vide* notification No. 14/25/2012-DGAD, dated the 10th October, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 10th October, 2014, has come to the conclusion that -

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below the associated normal values, thus resulting in dumping of the subject goods;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury in respect of the subject goods; and
- (iii) the dumped imports of the subject goods from the subject countries have caused material injury to the domestic industry.

and had recommended imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries in order to remove the injury to the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 48/2014-Customs (ADD), dated the 11th December, 2014, published *vide* G.S.R. 885 (E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th December, 2014;

And whereas, M/s Tariq Glass Industries Limited, Pakistan (exporter) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new

shipper review notification No. 15/16/2015-DGAD, dated 23rd September, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th September, 2015, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated party till the completion of the review by it:

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from subject countries through the said exporter namely, M/s Tariq Glass Industries Limited, Pakistan and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti-dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from subject countries through the said exporter namely, M/s Tariq Glass Industries Limited, Pakistan and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/46/2014-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.